कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत कृषि अखबार
Postal R.No.MP/BPL/525/2025-27 RNI No. Raj HIN/2000/3239, डाक प्रेषण का दिन- मंगलवार, बुधवार

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर
ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 जयपुर, प्रकाशन सोमवार, 12 जनवरी 2026 वर्ष-26 अंक-16 मूल्य-12/- कुल पृष्ठ-12 www.krishakjagat.org पृष्ठ-1

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें

श्रेष्ठ कृषि पत्रकारिता के लिए भाकृअनुप ICAR चौधरी चरणसिंह अवार्ड से पुरस्कृत

अंदर पढ़िये...

5

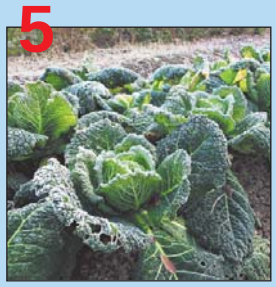

पाले से फसलों के बचाव के उपाय

किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व संवाद

आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प में कृषि, पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान और पशुपालक राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्तंभ है। राज्य सरकार इनको उन्नत, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए निरंतर फैसले ले रही है। श्री शर्मा ने कहा कि कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करते हुए ये तीनों क्षेत्र आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों में पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के गठन के तुरंत बाद राज्य के विकास का रोड मैप बनाते हुए कृषि क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताओं पानी और बिजली पर विशेष ध्यान दिया। पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगनहर, माही बांध एवं देवास परियोजना के कार्यों को आगे बढ़ाया गया। वहीं बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में भी लगातार कार्य करते हुए हमने वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया है।

किसानों को प्रतिवर्ष 3 हजार रुपये की अतिरिक्त सम्मान राशि- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को प्रतिवर्ष मिलने वाली 6 हजार रुपये की सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 हजार रुपये की सम्मान निधि दे रही है। अब तक राज्य सरकार द्वारा चार किस्तों में 72 लाख किसानों को 2 हजार 73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सम्मानि राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले दो साल में 921 करोड़ का अनुदान जारी कर 59 हजार से अधिक सौर पंप संयत्रों की स्थापना करवाई है। अब तक 17 लाख 30 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रदेश के कृषकों को निर्यातकों और खुदरा आपूर्ति समूहों से सीधे जोड़ने के लिए अब तक 913 कृषक उत्पादक संगठन पंजीकृत किए जा चुके हैं। श्री शर्मा ने कहा कि गत दो वर्ष में वर्षा जल संग्रहण के लिए 35 हजार से अधिक फार्म पौंड का निर्माण करवाया गया है और इसके लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। 34 हजार से अधिक किलोमीटर में खेतों पर तारबंदी के लिए 377 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। (**शेष पृष्ठ 3 पर**)

किसानों को नकली बीज-खाद-कीटनाशक से मिलेगी राहत : श्री शिवराज सिंह

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का डाक विभाग के साथ ऐतिहासिक एमओयू

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर पेम्मासानी की उपस्थिति में, नई दिल्ली में दो समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। पहला MoU कृषि और डाक विभाग के बीच कृषि इनपुट (बीज, उर्वरक, कीटनाशक) के सैंपलों की सुरक्षित ढुलाई के लिए था, जबकि दूसरा MoU ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग और DAY-NRLM ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार पर आधारित था। कार्यक्रम में कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह तथा डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

श्री चौहान ने कहा कि इन MoUs से किसानों को गुणवत्ता नियंत्रित कृषि इनपुट और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में मदद मिलेगी। श्री चौहान ने कहा कि घटिया बीज, खाद और कीटनाशक किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा है और अब सैंपलों की 'फेसलेस और ट्रेसलेस' ढुलाई से छेड़छाड़, देरी और मैनेजमेंट की गुंजाइश लगभग समाप्त हो जाएगी, जिससे प्रयोगशालाओं को समय पर और विश्वसनीय रिपोर्ट मिल सकेगी।

सर्वोत्तम गुणवत्तावाली
जैन ड्रिप की विस्तृत उत्पादन श्रृंखला -
सभी फसलों # के लिए हर किसान के बजट के अनुरूप विभिन्न प्रकार के ड्रिप सिचाई व्यवस्था के विकल्प स्टॉक में उपलब्ध हैं।
(# दलहन, धान, तिलहन, सब्जियाँ एवं फल बागानें आदि के लिए)

जैन टर्बो स्लिम - टीई व सुपर सेव्हर
5 से 20 मील (0.13 से 0.5 मिमी)
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन टर्बो एक्सेल प्लस
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन टर्बो लाईन सुपर
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी साईज

जैन टर्बो लाईन - पीसी
क्लास २
साईज - १६, २० मिमी

जैन टर्बो टॉप - एचडी पीसी
१३, १५ मील (०.33, ०.38 मिमी) - क्लास 1 व 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी

जैन पॉलीट्यूब एवं ड्रिपर्स
साईज - 12, 16, 20, 25, 32 मिमी

नोट : ड्रिपर्स व ड्रिपलाईन अलग-अलग प्रेशर रेटींग में उपलब्ध

जैन ड्रिप® प्रति बूँद, फसल भरपूर!®
जैन इरिगेशन सिस्टम्स् लि. छोटे छोटे कदम, आसमान छूने का दम!®
दूरभाष: 0257-2258011; 6600800
टोल फ्री : 1800 599 5000
ई-मेल: jisl@jains.com; वेबसाईट: www.jains.com

ड्रिपलाईन व फिटींग्ज | ड्रिपर्स | रेनपोर्ट स्प्रिंकलर | स्प्रे हेड व जेटस् | वॉल्व | फिल्टर्स | फिल्ट्रेशन संसाधन | फर्टिगेशन संसाधन | पीव्हीसी पाईप व फिटींग्ज | एचडीपीई पाईप्स व फिटींग्ज | क्विक कनेक्ट पाइप | ऑटोमेशन व कन्ट्रोलर्स

सावधान! नकल करके ड्रिप बनाने वाले एवं नकली ड्रिप कंपनियों और वितरकों से सतर्क रहें!

कृषि योजनाओं में केन्द्रीय धन राशि का समय पर उपयोग करें : श्री चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ की समीक्षा

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में गुजरात और पंजाब के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक कर दोनों राज्यों को निर्देश दिया कि केंद्र द्वारा दी गई धनराशि का समय पर, पारदर्शी और सही तरीके से उपयोग किया जाए, ताकि किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके। बैठक में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में राज्यवार योजनाओं की प्रगति, बजट का उपयोग और लंबित प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जिन राज्यों ने सही तरीके से धनराशि का उपयोग किया, उन्हें भविष्य में अधिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही, केंद्रीय मंत्री ने यह साफ किया कि केंद्र की राशि का ब्याज समय पर जमा करना अनिवार्य है, ताकि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके।

गुजरात में दलहन और तिलहन की उत्पादन क्षमता और एमएसपी पर खरीद की स्थिति पर संतोष जताते हुए उन्होंने उड़द की खरीद को तेज करने की बात कही। बैठक में पंजाब के कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, गुजरात के कृषि राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा, कृषि मंत्रालय के सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

भारत में नकली एग्रोकेमिकल व्यापार 1000 करोड़ के पार जाने की आशंका

राजकोट (कृषक जगत)। गुजरात में प्रवर्तन एजेंसियों ने नकली और मिलावटी एग्रोकेमिकल्स (कृषि रसायन) के निर्माण और वितरण के एक बड़े, संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस खुलासे ने किसानों की आजीविका, उपभोक्ता सुरक्षा और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की स्थिरता को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।

ताज़ा कार्रवाई 30 दिसंबर को राजकोट में की गई, जो 2025 के दौरान दर्ज कई एफआईआर और छापों की कड़ी का हिस्सा है। इससे पहले 20 नवंबर को अहमदाबाद, 12 अक्टूबर और 1 सितंबर को राजकोट में प्रवर्तन अभियान चलाए गए थे। जांचकर्ताओं का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ नकली एग्रोकेमिकल कारोबार के बढ़ते पैमाने और परिष्कृत तौर-तरीकों की ओर इशारा करती हैं, जहाँ उत्पाद अक्सर प्रतिष्ठित ब्रांडों के नाम पर बेचे जाते हैं।

नकद में लेन-देन

अधिकारियों का अनुमान है कि अवैध एग्रोकेमिकल व्यापार का मूल्य रू. 1,000 करोड़ से अधिक हो सकता है। एजेंसियों का मानना है कि कई ऑपरेटर अब भी सक्रिय हैं, जो देशभर में एजेंटों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के बहु-स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहे हैं। नियामकीय निगरानी से बचने के लिए लेन-देन का एक बड़ा हिस्सा नकद में किया जाता है।

जांच में राजकोट को इन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बताया गया है। कई मामलों में 'बायो' विकल्प के रूप में बेचे गए उत्पादों में रासायनिक अवशेष पाए गए और वे केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CIB) में अनिवार्य पंजीकरण से भी वंचित थे।

उत्पादन में गिरावट

इसके व्यापक प्रभाव अत्यंत गंभीर हैं। फिक्की (FICCI) के 2015 के एक अध्ययन के अनुसार, यदि गैर-प्रामाणिक एग्रोकेमिकल उत्पादों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत हो, तो फसल उत्पादन में 4 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है—जिसका अर्थ है हर साल लगभग 10.6 मिलियन टन खाद्य उत्पादन का नुकसान।

इंटरनेशनल मार्किट में नुकसान

अध्ययन में यह भी चेतावनी दी गई थी कि लगभग 29 मिलियन टन खाद्यान्न (मूल्य लगभग 26 अरब डॉलर) और 3 मिलियन टन फल-सब्जियाँ (मूल्य लगभग 1.4 अरब डॉलर) निर्यात बाज़ारों में जोखिम में पड़ सकती हैं, जिससे किसानों, उद्योग और सरकार-सभी को भारी राजस्व हानि हो सकती है। चिंताजनक रूप से, नकली एग्रोकेमिकल्स और अवैध बीजों का वितरण केवल गुजरात तक सीमित नहीं है। प्रवर्तन एजेंसियों के अनुसार, ये उत्पाद महाराष्ट्र सहित पड़ोसी राज्यों में भी सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे व्यापक फसल क्षति हो रही है।

कृषक जगत संचालक निमिष गंगराड़े को एग्रीकल्चर इनोवेशन लीडरशिप अवॉर्ड

नई दिल्ली। कृषक जगत के संचालक और अंतरराष्ट्रीय पत्रिका Global Agriculture के संपादक निमिष गंगराडे, को नई दिल्ली में 'एग्रीकल्चर इनोवेशन लीडरशिप अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। वर्ष 2025 के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें सुश्री अनीता नायर द्वारा प्रदान किया गया- जो CEO, Havas Media (India & South East Asia), Ex-COO (Media & Branding), पतंजलि रह चुकी हैं तथा वर्तमान में India Influencer Governing Council की बोर्ड एडवाइज़र हैं। 'यह पुरस्कार कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय नवाचार और योगदान के लिए दिया गया।

संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा

नई दिल्ली (कृषक जगत)। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। केंद्रीय बजट एक फरवरी (रविवार) को पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र की जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। उन्होंने बताया कि पहला चरण 13 फरवरी 2026 को खत्म होगा और संसद 9 मार्च 2026 को फिर से शुरू होगी। भारत सरकार की सिफारिश पर, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को 2026 के बजट सत्र के लिए बुलाने की मंजूरी दे दी है।

देश में रबी बुवाई 16 लाख हेक्टेयर बढ़ी

अब तक 634 लाख हेक्टेयर में हुई बोनी

नई दिल्ली (कृषक जगत)। देश में रबी फसलों की बुवाई समाप्ति की ओर है। अब तक गत वर्ष की तुलना में 16.40 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में बोनी हो गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2 जनवरी 2026 तक कुल 634.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई पूरी हो गई है। जबकि गत वर्ष अब तक 617.74 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। वहीं गेहूं की बोनी 334.17 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है जबकि गत वर्ष समान अवधि में 329.04 लाख हेक्टेयर हुई थी।

इस वर्ष देश की प्रमुख रबी फसल गेहूं का क्षेत्र बढ़कर 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले वर्ष से 6.13 लाख हेक्टेयर अधिक है। गत समान अवधि में 328.04 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। उधर धान की बुवाई भी 17.57 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई, जो गत वर्ष समान अवधि में 14.90 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी।

दलहन : दालों के कुल रकबे में 3.44 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 134.30 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। चना 95.88 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया, जिसमें 4.66 लाख हेक्टेयर की बढ़त दर्ज हुई।

मोटा अनाज : सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही 'श्री अन्न' (मिलेट्स) श्रेणी में भी ठोस वृद्धि देखी गई। इन फसलों के तहत क्षेत्र बढ़कर 51.79 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है जो गत वर्ष समान अवधि में 50.66 लाख हेक्टेयर था।

तिलहन : तिलहन फसलों की बुवाई में इस वर्ष अच्छा सुधार देखने को मिला है और कुल क्षेत्रफल में 3.04 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। तिलहनों में सबसे अधिक बढ़ोतरी रेपसीड और सरसों में हुई, जिनका क्षेत्र बढ़कर 89.36 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है जो पिछले वर्ष समान अवधि में 86.57 लाख हेक्टेयर था।

प्रमुख रबी फसलों की बुवाई
2 जनवरी 2026 की स्थिति (लाख हे. में)

फसल	सामान्य क्षेत्र	बुवाई 2025-26	बुवाई 2024-25
गेहूँ	**312.35**	**334.17**	**328.04**
चावल	**42.93**	**17.57**	**14.90**
दालें	**140.42**	**134.30**	**130.87**
चना	100.99	95.88	91.22
मोटे अनाज	**55.33**	**51.79**	**50.66**
ज्वार	24.62	20.74	22.00
मक्का	23.61	23.32	21.87
तिलहन	**86.78**	**96.30**	**93.27**
सरसों	79.17	89.36	86.57
कुल	**637.81**	**634.14**	**617.74**

नोट : कुल क्षेत्रफल के आंकड़े चार्ट से अलग हैं, क्योंकि सभी फसलों को चार्ट में शामिल नहीं किया गया है। स्त्रोत : कृषि मंत्रालय

'सहकार से समृद्धि' पर सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस

सहकारिता क्षेत्र को मजबूत, पेशेवर और व्यावसायिक मॉडल के रूप में विकसित करना आवश्यक : डॉ. भूटानी

जयपुर। सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लेक सिटी उदयपुर में आयोजित की जा रही राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया। इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत 12 सत्रों में 'सहकार से समृद्धि' की पहलों की समीक्षा की गई तथा भविष्य के रोडमैप पर भी मंथन किया गया।

कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को पारंपरिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाकर एक मजबूत, पेशेवर और व्यावसायिक मॉडल के रूप में विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में हुई गहन चर्चाओं, प्रजेंटेशन और फीडबैक सत्रों को अत्यंत उपयोगी बताया। डॉ. भूटानी ने कहा कि पैक्स सहकारी व्यवस्था की रीढ़ है, इनके कम्प्यूटरीकरण व डिजिटलीकरण से पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने अनाज भंडारण को मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि सहकारिता के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर कार्य किया जा रहा है। योजना के तहत सितंबर, 2026 तक 5 लाख मीट्रिक टन और सितंबर, 2027 तक 50 लाख मीट्रिक टन क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने निर्धारित समय में तय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित निगरानी पर भी बल दिया। डॉ. भूटानी ने सहकारी समितियों में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत नियमों के सरलीकरण, सदस्यता बढ़ाने, बेस्ट प्रेक्टिसेज के आदान-प्रदान पर जोर देते हुए 'भारत टैक्सी' जैसी नई पहलों का भी उल्लेख किया। मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सिद्धार्थ जैन ने कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

इससे पूर्व कॉन्फ्रेंस के द्वितीय दिन विभिन्न तकनीकी एवं विषयगत सत्रों का आयोजन हुआ, जिनमें पैक्स एवं सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर गहन विचार-विमर्श किया गया। 'सहकार से समृद्धि - पैक्स अहैड' सैशन में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को सशक्त एवं पुनर्जीवित करने में सहकारी बैंकों की भूमिका, कैशलेश पैक्स, सहकारिता स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिला-विशिष्ट व्यवसाय योजनाएं, मॉडल सहकारी ग्राम एवं सदस्यता अभियान आदि पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

पशुपालन मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं का किया समाधान

जयपुर। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने पाली जिले के सुमेरपुर तहसील मुख्यालय और विभिन्न गांवों में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर जाकर स्थिति देखने व नियमानुसार समाधान करने के निर्देया दिए।

उन्होंने कहा कि जनहित से सम्बंधित समस्याओं का त्वरित समाधान राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से सभी पात्रों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ दिलवाने की अपील की। श्री कुमावत ने सुमेरपुर स्थित अपने घर पर श्री कृष्ण भक्त गुरुदेव दाताश्री महेंद्रानंद गिरी जी महाराज गादीपति श्री कृष्ण धाम गुडा मांगलियान का शॉल ओढाकर व फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। देवस्थान मंत्री ने पोमावा स्थित जोडेवाला मामाजी मंदिर पहुंचकर श्री मामाधणी किरवा वीर के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की ।

मुख्य सचिव ने की समीक्षा

पीएम-कुसुम में मार्च 2026 तक विकसित करें 3 हजार मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं

राजस्थान विकेन्द्रित सौर ऊर्जा का हब बनकर उभरा

जयपुर। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि किसानों को सस्ती एवं सर्वसुलभ सौर ऊर्जा से जोड़ने की दृष्टि से पीएम-कुसुम योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजस्थान डिस्कॉम्स को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन को और गति प्रदान करते हुए आवंटित लक्ष्यों को चरणबद्ध रूप से हासिल करने की कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च-2026 तक 3 हजार मेगावाट की परियोजनाएं विकसित की जाएं।

मुख्य सचिव ने शासन सचिवालय में पीएम-कुसुम योजना तथा विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में विगत समय में राजस्थान विकेन्द्रित सौर ऊर्जा का हब बनकर उभरा है। कुसुम कम्पोनेंट-ए में सर्वाधिक क्षमता की विकेन्द्रित सौर परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। वहीं कम्पोनेंट-सी में राजस्थान देश में दूसरा अग्रणी राज्य बन गया है। डिस्कॉम्स दोनों ही घटकों में प्रदेश को सिरमौर बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने के लक्ष्य के साथ जुटें।

मुख्य सचिव ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस योजना के माध्यम से आज प्रदेश में 1 लाख 75 हजार किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली सुलभ हो रही है और प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके जरिए प्रदेश के सौर ऊर्जा क्षेत्र में 40 हजार करोड़ का निवेश होने जा रहा है जो कि निश्चय ही अभूतपूर्व उपलब्धि है।

मुख्य सचिव ने कहा कि कम्पोनेंट-ए में भारत सरकार द्वारा आवंटित 5250 मेगावाट तथा कम्पोनेंट-सी में 5367 मेगावाट के स्वीकृत लक्ष्यों पर आगे बढ़ते हुए दोनों घटकों में कुल 10 हजार 634 मेगावाट क्षमता के बिजली खरीद अनुबंध सम्पादित किए जा चुके हैं। उन्होंने इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द स्थापित करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने कम्पोनेंट-सी में केन्द्रीय वित्तीय सहयोग के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर उचित समन्वय करने के निर्देश दिए ताकि सौर परियोजनाएं विकसित करने वाले किसानों तथा डवलपरों को यथाशीघ्र सहायता सुलभ कराई जा सके।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री अजिताभ शर्मा ने मुख्य सचिव को आश्वस्त किया कि निचले स्तर तक बेहतर मॉनीटरिंग से निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा।

प्रमुख सचिव कृषि मंजू राजपाल ने कुसुम योजना के घटक बी की प्रगति के बारे में बताया।

राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने अवगत कराया कि विगत दो वर्ष में जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा कुसुम योजना में धरातल पर काम किया गया है। इसका परिणाम है कि राज्य में 2700 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं विकसित की जा चुकी हैं। विगत दो वर्ष में 70,381 कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री केपी वर्मा ने भी प्रगति की जानकारी दी।

किसानों, पशुपालकों, डेयरी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किसानों की बढ़ रही आय, उत्पादों को मिल रही विश्व में पहचान-

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 में अन्य उद्योगों के साथ कृषि और इससे जुड़े उद्योगों को विभिन्न प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। हमने 3 हजार 229 प्याज भंडारगृहों का निर्माण करवाया है, जिनके लिए करीब 45 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। राज्य के स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सोजत की मेहंदी एवं नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिल चुका है। नागौरी पान मेथी, कैर, सांगरी, बीकानेरी मोठ, बारां के लहसुन और मारवाड़ी काचरी के जीआई टैग प्रक्रिया में है। उन्होंने कृषकों से आग्रह किया कि कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों का सीमित मात्रा में उपयोग करें जिससे भूमि का उपजाऊपन बना रहे।

विभिन्न फैसलों से पशुपालकों का हुआ सशक्तीकरण-

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनका सशक्तीकरण किया है। पशुधन की असमय मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अब तक 12 लाख से अधिक पशुओं का नि:शुल्क बीमा किया गया है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल वेटेरिनरी सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। इसके तहत अब तक 536 मोबाइल वाहनों द्वारा करीब 60 लाख पशुओं का उपचार किया गया है। पशुओं के इलाज के लिए मुफ्त दवाओं की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों और पशुपालकों को आय में वृद्धि के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत हम दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दे रहे हैं। इसके तहत अब तक 5 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 1 हजार 300 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पंजीकृत गौशालाओं में बड़े पशु के लिए प्रतिदिन 50 रुपये और छोटे पशु के लिए प्रतिदिन 25 रुपये का अनुदान भी दे रही है। गौशालाओं को अब तक 3 हजार 432 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि गोपाल रत्न अवॉर्ड 2025 के तहत राजस्थान को देश में सबसे ज्यादा 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं।

बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों, पशुपालकों एवं डेयरी संघों के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार द्वारा कृषकों व पशुपालकों के हित में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कम लागत और अधिक आय वाली फसलों का उत्पादन बढ़ाने, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने, महिला कृषकों को और अधिक सशक्त बनाने जैसे सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सकारात्मक और महत्वपूर्ण सुझावों को आगामी राज्य बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

इस अवसर पर राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सी.आर. चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती मंजू राजपाल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में किसान, पशुपालक एवं डेयरी संघों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार बोन्द्रिया द्वारा संदीप शर्मा मे. संदीप इन्टरप्राइजेस, एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित एवं पेपर प्रिंट इंडस्ट्रीज 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश) से मुद्रित, सम्पादक : सुनील गंगराड़े, समन्वयक : रीतेश कोंडले. इस अंक का मूल्य रुपये 12/- वार्षिक शुल्क रुपये 600/- भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रं. Raj/HIN/2000/3239

कृषक जगत
संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्द्रिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े
अमृत जगत
शब्द से ही सृष्टि का उद्गम है और उसी से सृष्टि का विनाश।
- गुरुनानक देव

रबी फसलों का सही रखरखाव

रबी फसलों के लिये प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ाकर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाना संभव है। रबी का राजा गेहूं की तीन-चार स्थिति में बुवाई की जाती है। इसकी भरपूर उपज लेने के लिए खेत की तैयारी, उर्वरकों का उपयोग समय से बुआई, ये जरूरी कार्य है, जिन्हें प्राथमिकता से किया जाना होगा। अच्छी फसल के लिए 4-5 सिंचाई जरूरी होगी, जो फसल की विभिन्न अवस्था में दिया जाना चाहिए उनमें सबसे अहम सिंचाई बुआई के 21 दिनों बाद किरीट जड़ अवस्था में की जाना चाहिए, दूसरी सिंचाई कल्ले निकलते समय, चौथी फूल एवं दूधिया अवस्था तथा पांचवीं दाना बनते समय की जाना चाहिए। इस वर्ष की वर्षा से भूमिगत जल की स्थिति बेहतर हुई है। इस कारण भरपूर उर्वरक देकर अधिक उपज प्राप्त हो सकती है। विशेषकर बारानी खेती में भी नत्रजन, स्फुर तथा पोटाश तीनों मुख्य तत्व दिये जाना हितकर होगा। सिंचित गेहूं में प्रमुख तत्वों के अलावा जिंक तथा सल्फर का उपयोग भी उपयोगी होगा। अच्छी वर्षा से खरपतवार की बढ़वार भी अधिक हुई है। गेहूं में बथुआ की स्थिति तो कहीं-कहीं मुख्य फसल से अधिक भी हो सकती है इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अंकुरण उपरांत 30-35 दिनों के अंदर खरपतवारनाशी छिड़काव और एक निंदाई हाथ से हो जाये तो क्या कहने फसल देखते ही बनेगी। हाथ से निंदाई करने से दो पौधों के बीच हुए खरपतवार को

हटाना जरूरी होगा क्योंकि ये पौधों से, मुख्य रूप से बराबरी का पोषक तत्व खा लेता है जड़ सहित उखड़ने से उसका पुनः पनपने पर रोक लगेगी। कम उपजाऊ क्षेत्र में गेहूं की जगह जौ लगाना चाहिए कम लागत में अच्छा उत्पादन मिल सकेगा। दो पानी एक कल्ले निकलते समय तथा दूसरा फूल आने के समय यदि मिल जाये तो सोने में सुहागा हो जायेगा। चना, मटर, मसूर, अलसी, दलहनी फसल भी रबी की मुख्य फसलें हैं। आमतौर पर इनकी बुआई के लिये खेत की तैयारी में कोताही रखरखाव में कमी उर्वरकों का उपयोग नहीं के बराबर होने से इनकी औसत उपज पर असर होता है। इनके अच्छे उत्पादन के लिए अधिक ध्यान दिया जाना वर्तमान की जरूरत है। दलहनी फसलों में जड़ों का विकास एवं जड़ ग्रंथियों के विस्तार के लिए फास्फोरस खाद का दिया जाना महत्वपूर्ण है। बीजों का उपचार राइजोबियम कल्चर द्वारा बहुत जरूरी कार्य होगा। फूल आते समय एवं फलियां बनते समय सिंचाई करके उत्पादन दो गुना किया जा सकता है। चने की दुश्मन इल्ली के बचाव हेतु (अ) टी आकार की खूंटियां, प्रकाश प्रपंच तथा फेरोमेन ट्रेप का उपयोग अत्यंत लाभकारी होगा। इससे कीट नियंत्रण आसानी से होगा और समय से उपचार भी किया जा सकेगा। इसी प्रकार तिलहनी फसलों की बुआई से लेकर रखरखाव भी गेहूं की तरह की जाना चाहिए। उर्वरकों का उपयोग विशेषकर फास्फोरस एवं पोटाश से लाभ ही होगा इसके अलावा गंधक का उपयोग भी जरूरी होगा। शाखायें फूटते समय तथा फली अवस्था में यथासम्भव सिंचाई करने से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। रबी में मौसम मेहरबान रहता है। भरपूर प्रकाश, ऊर्जा तथा आर्द्रता जिसका लाभ उठाया जाकर लक्षित उत्पादन प्राप्त करना कठिन नहीं है।

'मनरेगा' को मारकर आया 'जी राम जी'

● योगेन्द्र यादव

विपक्ष को ऐतराज़ है कि जिस ऐतिहासिक योजना को देश 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' उर्फ 'मनरेगा' के नाम से जानता रहा है, उसके नाम से महात्मा गांधी को क्यों हटाया जा रहा है। यूँ भी सरकार द्वारा पारित नया नाम– 'विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक' उर्फ ''वीबी-जी राम जी विधेयक'–काफ़ी अटपटा था। पहले अंग्रेज़ी के 'एक्रोनिम' को सोचकर हिंदी के शब्द गढ़ने के इस तरीके में मैकॉले की गंध आती थी, लेकिन 'मनरेगा' की जगह सरकार द्वारा लाए जा रहे नए कानून का मसौदा देखकर लगा कि सरकार ने महात्मा गांधी का नाम मिटाकर ठीक ही किया। जब इस योजना की आत्मा ही नहीं बची, जब इसके मूल प्रावधान ही खत्म किए जा रहे हैं, तो नाम बचाने का क्या फ़ायदा।

पहले समझ लें कि 'मनरेगा' नामक यह क़ानून क्यों ऐतिहासिक था। आज़ादी के कोई साठ साल बाद भारत सरकार ने इस क़ानून के ज़रिए पहली बार अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने की दिशा में एक कदम उठाया था। संविधान के 'नीति निर्देशक सिद्धांत' के तहत 'अनुच्छेद 39(a) और 41' सरकार को हर व्यक्ति के लिए 'आजीविका के साधन' और 'रोजगार का अधिकार' सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। छह दशकों तक इसकी अनदेखी करने के बाद वर्ष 2005 में 'संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन' (यूपीए) सरकार ने संसद में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' पास किया और पहली बार देश के अंतिम व्यक्ति को इस बाबत एक हक दिया। यह कानून सम्पूर्ण अर्थ में रोजगार की गारंटी नहीं था, लेकिन इसके प्रावधान किसी सामान्य सरकारी रोजगार योजना से अलग थे।

यह क़ानून ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि वह सरकार से रोजगार की माँग कर सके। इसमें सरकारी अफ़सरों के पास किंतु-परंतु या बहानेबाजी की गुंजाइश बहुत कम छोड़ी गई थी। इस योजना का लाभ लेने की कोई पात्रता नहीं है। कोई भी ग्रामीण व्यक्ति अपने 'जॉब कार्ड' बनवाकर इसका लाभ उठा सकता है। रोजगार मांगने के लिए कोई शर्त नहीं है - जब भी रोजगार मांगा जाए, उसके दो सप्ताह में सरकार या तो उस व्यक्ति को काम देगी या फिर मुआवजा। इस योजना का अनूठा प्रावधान यह है कि इसमें बजट की कोई सीमा नहीं है - जब भी, जितने लोग चाहें, काम माँग सकते हैं और केंद्र सरकार को पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इस तरह अधूरा ही सही, लेकिन पहली बार रोज़गार के अधिकार को क़ानूनी जामा पहनाने की कोशिश हुई। दुनिया भर में इस योजना पर चर्चा हुई थी।

व्यवहार में यह क़ानून अपनी सही भावना के अनुरूप कुछ साल ही लागू हो पाया। 'मनरेगा' की दिहाड़ी बहुत कम थी और सरकारी बंदिशें बहुत ज़्यादा। फिर भी मनमोहन सिंह सरकार ने इसका विस्तार किया। 'यूपीए' सरकार जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क़ानून की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि वे इसे 'यूपीए' के शेखचिल्लीपन के म्यूज़ियम के रूप में बचाए रखेंगे। पहले कुछ वर्षों मोदी सरकार ने इस योजना का गाला घोंटने की कोशिश भी की, लेकिन 'कोविड' आपदा के समय मोदी सरकार को इसी योजना का सहारा लेना पड़ा। सरकार की कोताही, अफसरशाही की बदनीयत और स्थानीय भ्रष्टाचार के बावजूद 'मनरेगा' ग्रामीण भारत के अंतिम व्यक्ति के लिए सहारा साबित हुई।

पिछले 15 वर्षों में इस योजना के चलते 4,000 करोड़ दिहाड़ी रोजगार दिया गया। ग्रामीण भारत में इस योजना के चलते 9.5 करोड़ काम पूरे हुए। हर वर्ष कोई 5 करोड़ परिवार इस योजना का फायदा उठाते रहे। इस योजना के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ी। 'कोविड' जैसे राष्ट्रीय संकट या अकाल जैसी स्थानीय आपदा के दौरान 'मनरेगा' ने लाखों परिवारों को भूख से बचाया, करोड़ों लोगों को पलायन से रोका।

बीस साल पहले जिस संसद ने रोजगार की मांग आधारित गारंटी के जिस अनूठे कानून को सर्वसम्मति से पारित किया था, उसी संसद ने अभी पिछले हफ्ते उसी कानून को खारिज कर नए 'वीबी - जी राम जी' कानून को नए, विकसित भारत के लिए मंजूर किया है। क्या यह नया कानून किसी तरह भी रोजगार गारंटी को बरकरार रख पाएगा?

अब मोदी सरकार ने इस ऐतिहासिक योजना को दफन करने का मन बना लिया है। जाहिर है, ऐसी किसी योजना को औपचारिक रूप से समाप्त करने से राजनीतिक घाटा होने का अंदेशा बना रहता है। इसलिए घोषणा यह हुई है कि योजना को 'संशोधित' किया जा रहा है। झाँसा देने के लिए यह भी लिख दिया गया कि अब 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी, लेकिन यह गिनती तो तब शुरू होगी जब यह योजना लागू होगी, जब इसके तहत रोजगार दिया जाएगा। हकीकत यह है कि सरकार द्वारा संसद में पारित 'वीबी जी राम जी विधेयक' एक तरह से रोजगार गारंटी के विचार को ही ख़त्म करता है। अब यह हर हाथ को काम के अधिकार की बजाय चुनिंदा लाभार्थियों को दिहाड़ी के दान की योजना बन जाएगी।

सरकार ने इस योजना का हर महत्वपूर्ण प्रावधान पलट दिया है। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य में और उस राज्य के किस इलाके में रोजगार के अवसर दिए जाएँगे। केंद्र सरकार हर राज्य के लिए बजट की सीमा तय करेगी। राज्य सरकार तय करेगी कि खेती में मजदूरी के मौसम में किन दो महीनों में इस योजना को स्थगित किया जाएगा। अब स्थानीय स्तर पर क्या काम होगा, उसका फैसला भी ऊपर से निर्देशों के अनुसार होगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब इसका खर्चा उठाने की ज़िम्मेवारी राज्य सरकारों पर भी डाल दी गई है।

पहले केंद्र सरकार 90 प्रतिशत खर्च वहन करती थी, अब सिर्फ़ 60 प्रतिशत देगी। जिन ग़रीब इलाक़ों में रोज़गार गारंटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ की ग़रीब सरकारों के पास इतना फण्ड होगा ही नहीं और केंद्र सरकार अपने हाथ झाड़ लेगी। यानी ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हाँ, अगर किसी राज्य में चुनाव जीतने की मजबूरी हुई तो वहाँ अचानक रोज़गार गारंटी का फण्ड आ जाएगा। जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ इस योजना को या तो लागू नहीं किया जाएगा, या फिर उसकी सख़्त शर्तें लगायी जायेंगी। अच्छा हुआ जो ऐसी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। जिन्हें गांधी का विचार प्यारा है उन्हें संसद में इस विधेयक के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी होगी, उन्हें देश के मानस में 'मनरेगा' की हत्या की ख़बर पहुचानी होगी, उन्हें किसानों की तरह सड़क पर संघर्ष करना होगा। **(सप्रेस)**

पाले से फसलों के बचाव के उपाय

वर्तमान में शीतलहर तथा अधिक ठंडी के कारण पाला पड़ने की संभावना एवं उससे बचाव की सलाह यहां किसान भाइयों को दी जा रही है। जिसे अपनाकर काफी हद तक फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। लगातार उत्तर एवं पश्चिम से ठंडी हवाएं एवं बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट होने के कारण फसलों एवं उद्यानिकी फसलों पर पाला पड़ने की संभावना बढ़ गई है। जो आगे भी बने रहने की संभावना है।

पाला मुख्यतः दो तरह का होता है पहला समानान्तर पाला एवं दूसरा विकिरण द्वारा पाला। शीतलहर में ठंडी हवाएं चलने के कारण तथा विकिरण पाला तब पड़ता है जब हवा शांत हो तथा आसमान बिल्कुल साफ हो उस दिन पाला पड़ने की संभावना रहती है। पाला तब पड़ता है जब तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होते हुए शून्य डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तब पाला पड़ता है। ऐसी अवस्था में वायुमंडल के तापमान को शून्य डिग्री से ऊपर बनाए रखना जरूरी हो जाता है। पाले की अवस्था में पौधों के अंदर का पानी जम जाने से तथा उसका आयतन बढ़ने से पौधों की कोशिकाएं फट जाती हैं जिसके कारण पत्तियां झुलस जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होने से फसल में फल और फूल नहीं लगते तथा उपज बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त तापमान कई बार शून्य डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम हो जाता है तो ऐसी अवस्था में ओस की बूंदें पौधों पर जम जाती हैं जिसके कारण पौधों तथा उनकी फलियों और फूलों और पत्तों पर बर्फ जमा होने से ज्यादा नुकसान होता है। यदि पाला की यह अवस्था अधिक देर तक बनी रहे तो पौधे मर भी सकते हैं। पाला विशेषकर दिसंबर तथा जनवरी के महीने में ज्यादा पड़ने की संभावना रहती है। पाला के प्रभाव से प्रमुख रूप से उद्यानिकी फसलें जैसे टमाटर, बैंगन, आलू, फूलगोभी, मिर्च, धनिया, पालक तथा फसलों में प्रमुख रूप से मसूर चना तथा कुछ मात्रा में गेहूं आदि के प्रभावित होने की ज्यादा संभावना रहती है विशेषकर जब यह फूल और फल की अवस्था में हो। अतः पाले से बचाव के लिए यहां किसान भाइयों को कुछ विशेष उपयोगी सलाह दी जाती हैं जिससे कि समय रहते इसे अपनाकर काफी हद तक अपनी फसलों को बचा सकें।

पाला से फसलों का बचाव

- पाला पड़ने की संभावना होने पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वह रात्रि 10 बजे से पहले दिन में सिंचाई अवश्य करें। फसलों में सिंचाई रात्रि के दूसरे तथा तीसरे पहर में नहीं करें।
- पाला की आशंका होने पर फसलों तथा उद्यान की फसलों में घुलनशील गंधक 80 प्रतिशत डब्ल्यू पी का दो से ढाई ग्राम मात्रा को प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर डेढ़ से दो सौ लीटर पानी में घोलकर फसलों के ऊपर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। इससे दो से ढाई डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ने से काफी हद तक पाला से बचाया जा सकता है।
- बारानी फसलों में पाले की आशंका होने पर व्यावसायिक गंधक के तेजाब का 0.1 प्रतिशत के घोल का अर्थात् 1 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसलों के ऊपर छिड़काव करें परंतु ध्यान रखें की इसकी संतुलित और निश्चित मात्रा का ही प्रयोग करें अन्यथा फसल को नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार इसके स्थान पर थायो यूरिया का 0.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल की दर से छिड़काव करने से भी पाला से काफी हद तक फसलों को बचाया जा सकता है। प्रत्येक अवस्था में पानी की मात्रा प्रति एकड़ डेढ़ से दो सौ लीटर अवश्य रखें।
- पाला से सबसे अधिक नुकसान नर्सरी में होता है। इसलिए रात्रि के समय नर्सरी में लगे पौधों को प्लास्टिक की चादर से ढक करके बचाया जा सकता है। ऐसा करने से प्लास्टिक के अंदर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है जिसके कारण तापमान जमाव बिंदु तक नहीं पहुंचता है और पौधे पाला से बच जाते हैं। लेकिन यह तकनीकी कम क्षेत्र के लिए उपयोगी है। जिन किसान भाइयों ने 1 से 2 वर्ष के फलदार पौधों का अपने खेतों में वृक्षारोपण किया हो उन्हें बचाने के लिए पुआल, घास–फूस आदि से अथवा प्लास्टिक की सहायता से ढककर बचायें। प्लास्टिक की सहायता से क्लोच अथवा टाटिया बनाकर पौधों को ढक देने से भी पाला से रक्षा होती है। इसके अलावा थालों के चारों ओर मल्चिंग करके सिंचाई करते रहें।
- दिसंबर से फरवरी माह तक अधिक ठंड पड़ने के कारण पशु तथा बछड़ों आदि को भी रात्रि के समय घरों के अंदर बांधें तथा उन्हें बोरे तथा जूट के बोरे तथा टाट–पट्टी से ओढ़ाकर ठंठ से बचायें। इसी प्रकार मुर्गी तथा बकरी घर को भी चारों तरफ से पॉलीथिन की सीट या टाट–पट्टी आदि से बांधकर ठंडी हवाओं से चारों तरफ से बचायें।
- छोटे किसान भाई जहां पर खेतों का क्षेत्रफल कम हो वहाँ मध्यरात्रि के बाद मेड़ों के ऊपर उत्तर तथा पश्चिम की तरफ घास–फूस आदि में थोड़ा नमी बनाकर जलाकर धुआ करें हालांकि यह प्रक्रिया पर्यावरणीय दृष्टि से उचित नहीं है पर इससे भी पाला से बचाव में सहायता मिलती है।
- ज्यादा ठंड तथा पाला पड़ने पर मनुष्यों एवं बच्चों को भी सलाह दी जाती है कि वह रात्रि के तीसरे और चौथे पहर में खेतों की मेड़ों पर या यहाँ–वहाँ न घूमें। तथा गर्म कपड़े आदि पहन कर घर में ही रहें एवं सूर्योदय के बाद ही घर से निकलने की सलाह दी जाती है।

चने में बेहतर उत्पादन के लिये करें कीट प्रबंधन

रबी मौसम में कृषकों को सलाह दी जा रही है कि वर्तमान में चने की फसल फूल एवं फली अवस्था में और इसी अवस्था में चने की फसल में सबसे ज्यादा कीट एवं रोग का आक्रमण होता है अतः चने में कीट एवं रोग प्रबंधन अवश्य करें।

कीट

चना फसल का मुख्य कीट चने की इल्ली (हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा) है, जो 15–20 प्रतिशत हानि पहुंचाता है। यह कीट कोमल पतियों, फूल तथा फलियों में छेद कर दाने खाता है। इस कीट के प्रकोप को एकीकृत कीट प्रबंधन से रोका जा सकता है।

नियंत्रण

- खेत में प्रकाश प्रपंच एवं फेरोमेन प्रपंच लगायें। खेत में पक्षियों के बैठने हेतु अंग्रेजी अक्षर T आकार की 50 खूटियां प्रति हेक्टर के हिसाब से समान अंतर पर लगाएं।
- नीम बीज सत 5 प्रतिशत का उपयोग करें।
- परजीवी रोगाणु ट्राइकोग्रामा आदि का उपयोग भी किया जा सकता है।
- श्यामा तुलसी व गेंदा के पौधे बीच में लगाने से इल्ली नहीं लगती।
- अंतरवर्तीय फसलें लगाने से कीटों से नुकसान कम होता है।
- खेत के खरपतवार नष्ट करें तथा गर्मी में गहरी जुताई करें।

रोग

चना में उकटा रोग का प्रकोप मुख्य रूप से होता है, इस रोग से पौधे मुरझा कर सूख जाते हैं, चना के अन्य रोग जैसे पद गलन या पद विगलन रोग जड़ सड़न अल्टरनेरिया झुलसा रोग आदि हैं। रोग नियंत्रण इस प्रकार करें।

नियंत्रण

- रोगी पौधे को निकाल कर जला दें।
- इस रोग से ग्रसित बीजों को काम में न लें।
- चने के साथ गेहूं, सरसों या अंतरवर्तीय फसलों को बोयें।
- फसल को अधिक बढ़वार से बचायें।
- रोग का प्रकोप होने पर डायथेन एम. 45 का 40 ग्राम प्रति टंकी (15 लीटर) की दर से घोल तैयार कर छिड़काव करें।

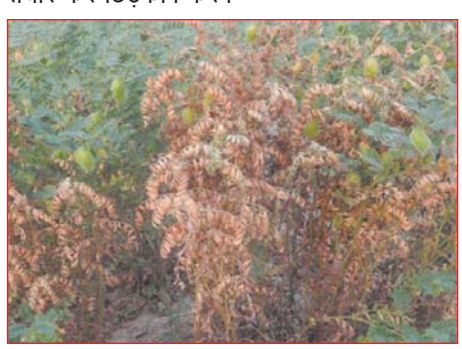

विटामिन से भरपूर गाजर की खेती

● संदीप कुमार शर्मा ● डॉ. संजय सिंह
● वैष्णवी दुबे

गाजर भारत की प्रमुख शीतकालीन सब्जी है, जो विटामिन- A , कैरोटीन, खनिज तत्व और रेशा प्रदान करने के कारण पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाल एवं नारंगी गाजर का उपयोग सलाद, जूस, हलवा, आचार, मुरब्बा और प्रोसेसिंग उद्योग में व्यापक रूप से होता है, जिससे इसकी बाजार मांग वर्षभर बनी रहती है। उच्च उत्पादन क्षमता, त्वरित नकद आय और कम अवधि की फसल होने के कारण गाजर उत्पादन किसानों के लिए लाभकारी विकल्प है।

जलवायु

गाजर ठंडी और शुष्क जलवायु में उत्कृष्ट गुणवत्ता की जड़ें बनाती है। 18-25°C तापमान जड़ वृद्धि, रंग, आकार और मिठास के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अत्यधिक गर्मी में जड़ें पतली और कड़वी हो सकती हैं, जबकि बहुत अधिक ठंड में जड़ निर्माण धीमा पड़ जाता है। कोहरे के मौसम में नियमित निगरानी जरूरी रहती है, ताकि रोगों का प्रकोप नियंत्रित रखा जा सके।

मिट्टी

गहरी, भुरभुरी, बलुई दोमट या दोमट मिट्टी गाजर उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है। अच्छी जल निकास क्षमता मिट्टी में आवश्यक है, ताकि जड़ सड़न की समस्या न हो। मिट्टी का पीएच 6-7 सबसे अनुकूल है। पथरीली, कड़ी या भारी चिकनी मिट्टी में जड़ें टेढ़ी-मेढ़ी तथा फटी हुई बनती हैं, जिससे उनकी बाजार गुणवत्ता घट जाती है। इसलिए मिट्टी को नरम व सूक्ष्म कणों वाली बनाना महत्वपूर्ण है।

प्रमुख किस्में

(क) देसी/ट्रॉपिकल किस्में

पूसा मेघाली, पूसा केसरी, पूसा रुधिरा, नैनिताल रेड—ये किस्में अधिक तापमान सहनशील हैं और मैदानी क्षेत्रों में अधिक उपयुक्त साबित होती हैं। इनकी जड़ें मोटी, गहरे लाल रंग की और मिठास वाली होती हैं।

(ख) यूरोपीय/टेम्परेट किस्में

नांतेस, पूसा यमदागनी, कुरोदा इम्प्रूव्ड, पूसा विशेष—ये किस्में ठंडे क्षेत्रों में उत्कृष्ट गुणवत्ता देती हैं। इनकी जड़ें मुलायम, चिकनी, चमकीली नारंगी और प्रोसेसिंग के लिए उत्तम मानी जाती हैं।

बुवाई का समय

उत्तर भारत में गाजर की मुख्य बुवाई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। पर्याप्त ठंड होने पर यूरोपीय किस्मों की बुवाई दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु ठंडी होने के कारण जुलाई से फरवरी तक बुवाई उपयुक्त रहती है। सही समय पर बुवाई करने से जड़ों की गुणवत्ता और उपज दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

भूमि की तैयारी

खेत की 2-3 गहरी जुताइयाँ कर मिट्टी को पूरी तरह भुरभुरी और ढेलामुक्त बना लें। अंतिम जुताई के समय 20-25 टन/हेक्टेयर गोबर की खाद, कम्पोस्ट या वर्मी-कम्पोस्ट मिलाने से मिट्टी की संरचना सुधरती है और जड़ें सीधी विकसित होती हैं। समतल क्यारियाँ या उठी हुई बेड (raised bed) बनाना विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि इससे जल निकास बेहतर रहता है और जड़ विकृति कम होती है।

बीज की मात्रा एवं बुवाई की विधि

गाजर के लिए 4-6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। पंक्ति-पंक्ति दूरी 30 सेमी तथा पौधा-पौधा दूरी 7-10 सेमी रखें। बीज को 1.5-2 सेमी गहराई पर बोएँ ताकि अंकुरण अधिकतम हो सके। हल्की नमी वाली मिट्टी में बुवाई कर तुरंत हल्की सिंचाई दें। बीज को बहुत गहराई पर डालने से अंकुरण कम हो जाता है।

पतला करना (Thinning)

अंकुरण के 20-25 दिन बाद थिनिंग करना आवश्यक है। पौधों के बीच उचित दूरी रखने से प्रत्येक पौधे को पर्याप्त पोषक तत्व, प्रकाश और स्थान मिलता है। इस प्रक्रिया से जड़ें मोटी, सीधी और बाजार योग्य आकार की बनती हैं। थिनिंग न करने पर पौधे कमजोर रह जाते हैं और जड़ें सूखी व पतली बनती हैं।

उर्वरक एवं पोषक तत्व प्रबंधन

मिट्टी परीक्षण उपलब्ध न हो तो सामान्य अनुशंसा के अनुसार प्रति हेक्टेयर 50-60 किग्रा नाइट्रोजन, 40 किग्रा फास्फोरस और 40 किग्रा पोटाश देना चाहिए। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा भूमि तैयारी के समय मिलाएँ तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बेसल डोज में दें। शेष नाइट्रोजन बुवाई के 30-35 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग करें।

बोरॉन की कमी वाले क्षेत्रों में 10-15 किग्रा बोरेक्स या 0.2 प्रतिशत बोरिक एसिड का छिड़काव करने से जड़ों में दरार, कड़ापन तथा काले धब्बों की समस्या कम होती है। जैव उर्वरकों (Azotobacter, PSB) का प्रयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है।

सिंचाई प्रबंधन

पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद करें। इसके बाद मौसम और मिट्टी की नमी के अनुसार 7-10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई दें। जल जमाव बिलकुल न होने दें, क्योंकि इससे जड़ों का गलना, फटना या दोमुखापन हो सकता है। नालियों की उचित व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।

खरपतवार प्रबंधन

शुरुआती 30-40 दिन गाजर के लिए अत्यंत संवेदनशील अवधि होती है। इस दौरान 2-3 निराइ-गुड़ाई अवश्य करें। रासायनिक नियंत्रण हेतु पेंडीमेथालिन 1.0 किग्रा सक्रिय तत्व/हेक्टेयर की दर से बुवाई के तुरंत बाद लेकिन अंकुरण से पहले छिड़काव किया जा सकता है।

खुदाई

गाजर की अधिकांश किस्में 90-120 दिन में तैयार हो जाती हैं। जब जड़ें उचित आकार, लंबाई और रंग प्राप्त कर लें, तब खुदाई करें। देर से खुदाई करने पर जड़ें रेशेदार और कठोर हो जाती हैं। खुदाई हमेशा सावधानीपूर्वक करें ताकि जड़ों को कटने या टूटने से बचाया जा सके।

उपज एवं बाद-कटाई प्रबंधन

उन्नत किस्मों व वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर किसान 250-300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर सकते हैं। खुदाई के बाद जड़ों की सफाई, छँटाई और ग्रेडिंग करें। गाजर को छायादार, ठंडे और हवादार स्थान में रखें या तुरंत बाजार/प्रोसेसिंग इकाई तक भेजें। उचित हैंडलिंग से ताजगी और गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है।

प्रमुख कीट, उनके लक्षण एवं प्रबंधन

एफिड्स

लक्षण: पत्तियों के निचले भाग पर छोटे हरे/काले कीट रस चूसकर पत्तियाँ पीली व मुड़ी हुई चिपचिपा पदार्थ (हनीड्यू) सूटी फफूंदी का विकास

प्रबंधन: प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल 5ब्र या नीम आधारित कीटनाशी गंभीर प्रकोप पर अनुशंसित कीटनाशी (जैसे इमिडाक्लोप्रिड) का सीमित उपयोग खेत में खरपतवार नियंत्रण और फसल चक्र अपनाएँ

कटवर्म

लक्षण: नव अंकुरित पौधों को रात में काटकर गिरा देना पौधों की संख्या में भारी कमी।

प्रबंधन: गहरी जुताई कर लार्वा को नष्ट करें शाम को खेत में प्रकाश आकर्षण ट्रैप लगाएँ खेत के किनारों पर पौधों के अवशेष जमा न होने दें।

जड़ मक्खी

लक्षण: पत्तियाँ लाल-बैंगनी रंग की जड़ों में छोटे छेद व गैलरी जड़ों का सड़ना व दुर्गंध।

प्रबंधन: फसल चक्र अपनाएँ, जड़ों पर मिट्टी चढ़ाते रहें ताकि मक्खी अंडे न दे सके,पीली चिपचिपी ट्रैप लगाए, संक्रमित जड़ों को खेत से हटाएँ।

प्रमुख रोग, लक्षण एवं प्रबंधन

अल्टरनेरिया ब्लाइट

लक्षण: पत्तियों पर भूरे-काले छल्लेदार धब्बे, पत्तियों का सूखना और गिरना।

प्रबंधन: रोगमुक्त बीज, रोग दिखते ही मैनकोजेब 2-2.5 ग्राम/लीटर का छिड़काव, खेत में पानी का जमाव न होने दें।

पत्ती धब्बा रोग

लक्षण: छोटे गोल भूरे धब्बे, बाद में धब्बे आपस में मिलकर पत्ती सुखा देते हैं।

प्रबंधन: उचित फास्फोरस-पोटाश, मैनकोजेब/ क्लोरोथैलोनिल का स्प्रे, संक्रमित पत्तियाँ हटाएँ।

जड़ गलन

लक्षण: जड़ें काली या भूरे रंग की, मुलायम, पौधा मुरझाने लगता है अधिकतर पानी रुकने पर।

प्रबंधन: जल निकास सुधारें, बुवाई से पूर्व बीज उपचार (कार्बेन्डाजिम/थिरम 2-3 ग्राम/किग्रा),खेत में अत्यधिक नमी से बचें।

मधुमक्खियों की प्रमुख शत्रु माईट एवं प्रबंधन

● डॉ. अभिषेक शुक्ला
कीट विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय
नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, वघई, गुजरात

मधुमक्खियाँ परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो सीधे वैश्विक कृषि और जैव-विविधता को प्रभावित करती हैं। अन्य जीवों की तरह मधुमक्खियों के भी कई ज्ञात प्राकृतिक शत्रु पाए जाते हैं। ये मधुमक्खी की दैनिक गतिविधियों, पराग एकत्रीकरण तथा प्रजनन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं। अनेक बीमारियों के समान ये प्राकृतिक शत्रु भी मधुमक्खियों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन परिस्थितियों में इन प्राकृतिक शत्रुओं की रोकथाम भी अत्यंत आवश्यक हो जाती है। इन प्राकृतिक शत्रुओं में विभिन्न प्रकार की माईट (वरूथी) का स्थान महत्वपूर्ण है इनमें वरोआ माईट, ट्रोपिलेप्स माईट और श्वसन को बाधित करने वाली ट्रेकियल माईट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत लेख में मधुमक्खियों को प्रभावित करने वाली इन्हीं भिन्न-भिन्न माईट के विषय में सविस्तार जानकारी देने का प्रयास किया गया है जो हमारे मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए उपयोगी साबित होगा।

परजीवी वरोआ माईट

परजीवी वरोआ माईट (वरोआ डिस्ट्रक्टर) दुनिया भर में मधुमक्खी आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में उभर रही है। वरोआ माईट नामक यह परजीवी देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में फैल गया है। एक जानकारी के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में शहद उद्योग को बचाने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मारा भी गया है। वहां अब तक 60 लाख से ज्यादा मधुमक्खियां मारी जा चुकी हैं। यह फैसला ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए लिया क्योंकि यह माईट अपने साथ विषाणु का भी फैलाव करने में अपनी भूमिका अदा कर रही है। यह वायरस मधुमक्खियों के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक, अगर यह वायरस फैला तो सिर्फ शहद उद्योग को 70 मिलियन डॉलर यानी करीब चार अरब रुपये का नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, इस परजीवी वायरस ने दुनिया के सभी देशों में मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाया है। वरोआ माईट, मधुमक्खी को कमजोर कर देता है। ये परजीवी मधुमक्खियों का रक्त चूसती हैं और उन्हें अपंग बना देती हैं जिसके कारण वे उड़ने में अक्षम हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में वरोआ माईट से ग्रसित हजारों मधुमक्खियों को नष्ट कर दिया गया है तथा मधुमक्खी पालकों को सतर्क रहने को कहा गया है। वरोआ माईट पहले एशिया, यूरोप, अमेरिका और न्यूजीलैंड में पायी जाती थी। इस परजीवी ने यूरोप में भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। जहां भी यह माईट पायी गयी है, वहां मधुमक्खियों की पूरी की पूरी कॉलोनियां नष्ट कर दी गई हैं। इस माईट का प्रभाव इतना खतरनाक होता है कि यह जिन मधुमक्खियों को ग्रसित करती है उन्हें कमजोर कर देती है, जिससे कॉलोनी में नई मधुमक्खियां अपंग पैदा होती है।

पहचान और हानि: ये परजीवी दिखने में लाल-भूरे रंग की होती है। वरोआ माईट एक तिल के आकार का परजीवी है जो मधुमक्खी के छत्ते पर हमला करती है। वरोआ माईट नग्न आंखों से मुश्किल से दिखाई देती है, इसका माप लगभग 1-1.8 मि. मी. है। वरोआ माईट एक बाह्यपरजीवी (एक्टोपैरासाईट) है जो विशेष रूप से मधुमक्खियों को निशाना बनाती है। ये माईट एशिया की मूल निवासी है। इस माईट ने सर्वप्रथम एशियाई मधुमक्खी (एपिस सेराना) को ग्रसित किया था। अब वरोआ माईट यूरोपीय मधुमक्खियों पर भी हमला करती पायी गयी है। यह माईट मधुमक्खी पालन में उपयोग होने वाले उपकरणों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती है साथ ही साथ एक परजीवित मधुमक्खी से दूसरी स्वस्थ मधुमक्खी तक फैलती है।

जीवन चक्र के दो मुख्य चरण: इस परजीवी माईट के जीवन चक्र दो अवस्थाओं में पूर्ण होती है: फ़ोरेटिक चरण तथा प्रजनन चरण।

फ़ोरेटिक चरण: वयस्क माईट, वयस्क मधुमक्खियों के शरीर से चिपक जाती हैं और मधुमक्खी का खून (हिमोलिम्फ) चूसती है तथा केवल वयस्क मादा वरोआ माईट ही वयस्क मधुमक्खियों का परजीवीकरण करती है। वयस्क नर केवल लार्वा और प्यूपा पर ही जीवन निर्वाह करते है और अंडे सेने के बाद वे ब्रूड कोशिकाएं भी नहीं छोड़ते है। इससे मधुमक्खियां कमजोर हो जाती हैं और उन्हें द्वितियक संक्रमणों और विषाणु संक्रमणों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

प्रजनन चरण: वयस्क मादा वेरोआ माईट प्रीकैपिंग चरण में मधुमक्खी ब्रूड कोशिकाओं (विशेष रूप से ड्रोन ब्रूड) में प्रवेश करती हैं और ब्रूड सेल बंद होने के बाद दो से पांच अंडे देती हैं। ये 0.5 मि. मी. लंबे अंडे कोशिकाओं के नीचे, दीवारों पर और कभी-कभी सीधे लार्वा पर रखे जाते हैं। पहले अंडे से नर निकलता है और दूसरे अंडे से तथा उसके बाद के अंडों से मादा पैदा होती है। अंडे सेने के बाद, वरोआ माईट वयस्क अवस्था में पहुँचने से पूर्व पहले दो लार्वा अवस्थाओं (जिन्हें 'प्रोटोनिम्फ' और 'ड्यूटोनिम्फ' कहा जाता है) से गुजरते है। नर वरोआ माईट को विकसित होने में लगभग 5 से 6 दिन और मादा माईट को 7 से 8 दिन लगते हैं। नर तथा मादा में समागमन प्रायः ब्रूड सेल में ही होता है। नर वरोआ माईट थोड़े समय के बाद कोशिका के भीतर मर जाते हैं। युवा मादा वरोआ माईट, विकसित होती हुई मधुमक्खी के साथ ब्रूड सेल से निकलती है। वरोआ माईट 2 सप्ताह के बाद अन्य ब्रूड कोशिकाओं में अंडे देती है। वयस्क मादा वरोआ माईट आमतौर पर 2 महीने तक जीवित रहती है।

वरोआ माईट के लक्षण और प्रभाव: कम संक्रमण वाली कालोनियों में आमतौर पर बहुत कम लक्षण दिखाई देते हैं, हालांकि जैसे-जैसे वरोआ माईट की संख्या बढ़ती है, इसकी उपस्थिति के लक्षण भी और अधिक स्पष्ट हो जाते है। वरोआ माईट का बहुत अधिक संक्रमण 3 से 4 वर्षों के भीतर दिखाई देता है और इसके परिणामस्वरूप मधुमक्खियों के अल्पविकसित शिशु, अपंग और ख़राब उड़ान वाली मधुमक्खियां, परागण के बाद कॉलोनी में मधुमक्खियों की वापसी की कम दर, मधुमक्खियों की आयु में कमी और श्रमिक मधुमक्खियों के वजन में कमी से प्रदर्शित होती है।

वरोआ प्रभावित कॉलोनी के लक्षण: जिन्हें आमतौर पर परजीवी वरोआ सिंड्रोम कहा जाता है, में असामान्य ब्रूड पैटर्न, धँसी हुई और चबाई हुई कैपिंग और कोशिका के नीचे या किनारे पर लार्वा शामिल हैं। यह अंततः मधुमक्खियों की आबादी में गिरावट और कॉलोनी के पतन और मृत्यु का कारण बनता है। यह मधुमक्खी कॉलोनियों पर कई हानिकारक प्रभाव डालता है जैसे कि -

शारीरिक विकार: प्रभावित मधुमक्खियों के पंख विकृत हो सकते हैं, उनका पेट छोटा हो सकता है और उनका बाह्यकंकाल कमजोर हो जाता है।

जीवन क्षमता में कमी: वरोआ माईट, श्रमिक मधुमक्खियों के जीवनकाल को छोटा कर देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों अपनी कॉलोनी का दैनिक काम काज कम कर देती है तथा इससे कालोनी की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है।

वायरस का फैलाव: वयस्क मादा वरोआ माईट बहुत सक्रिय होती है और छत्तों के आसपास या वयस्क मधुमक्खियों के बीच घूमती रहती है। इस व्यवहार का मतलब है कि वरोआ माईट एक प्रभावी वायरस वाहक के रूप में भी कार्य करती है तथा एक-एक मधुमक्खी के बीच वायरस को स्थानांतरित करती है। वरोआ माईट कई प्रकार के वायरस के वाहक का कार्य करती है इनमें विकृत पंख विषाणु (डिफोर्मड विंग वायरस) और एक्यूट बी पैरालिसिस विषाणु प्रमुख है।

प्रबंधन एवं नियंत्रण उपाय:

रासायनिक नियंत्रण: प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक एसिड और एसेंशियल तेल शामिल हैं। वरोआ माईट की आबादी को नियंत्रित करने के लिए फॉर्मिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड और लैक्टिक एसिड का उपयोग किया जाता है लेकिन इनके अत्यधिक उपयोग से वरोआ माईट में इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है अंतः इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

जैविक उपाय: वरोआ-प्रतिरोधी मधुमक्खी किस्मों का प्रजनन और उनका विकास करना इसका प्रमुख घटक है। इसमें मधुमक्खियों की ऐसी किस्मों का विकास करना जो स्वच्छ व्यवहार वाली (ग्रुमीग व्यवहार) होती है । वरोआ माइट नियंत्रण हेतु वरोआ माईट प्रतिरोधी मधुमक्खियों की किस्मों का उपयोग, रसायनों पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है।

यांत्रिक उपाय: ड्रोन ब्रूड हटाने की तकनीक वरोआ माईट की आबादी को कम करने में मदद करती है। वरोआ माईट से संक्रमित फ्रेमों को समय पर हटाने से वरोआ माईट की आबादी को कम किया जा सकता है।

निगरानी: चीनी शेक या अल्कोहल वॉश जैसी विधियों का उपयोग करके, वरोआ माईट की आबादी की नियमित रूप से निगरानी की जा सकती है और यह नियंत्रण का एक तरीका प्रदान कर सकता है। **(क्रमशः)**

वरोआ माईट का आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव

मधुमक्खी पालन पर वरोआ माईट का आर्थिक प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके संक्रमण के परिणामस्वरूप शहद का उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है, इनकी कॉलोनियाँ कमजोर हो जाती है और उपचार और प्रबंधन लागत का खर्च बहुत बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त, मधुमक्खियों द्वारा परागण सेवाएं, जो वैश्विक कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खतरे में पड़ गया है। जब मधुमक्खी कालोनियां पर्यावरणीय प्रभावों तथा वरोआ माईट से नष्ट हो जाती हैं, तो फसल की पैदावार पर बहुत अधिक प्रतिकूल असर पड़ता है तथा जैव विविधता में भी भारी गिरावट आती है। इससे कृषि के साथ-साथ प्राकृतिक पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है।

समस्या –समाधान

समस्या– भिण्डी की बसन्त में लगाई जाने वाली नवीनतम जातियों की जानकारी दें।

– किशन सिंह

समाधान– ● भिण्डी की नई जातियों में

प्रमुख है चंचल, कोमल, निर्मल तथा बरगुन्डी हैं चंचल जाति की भिण्डी 15 से 20 से.मी. लम्बी रहती हैं और यह बोनी के 40–45 दिन बाद पहले मुख्य तने तथा बाद में टहनियों पर फलती है। यह पीले मोजेक वाइरस के प्रति सहनशील है।

● कोमल जाति की भिण्डी 10–20 से.मी. लम्बी रहती है और यह बुआई के 48–50 दिन बाद फलने लगती है। यह जाति पीले मोजेक वायरस तथा भभूतिया रोग के प्रति सहनशील रहती है।

● निर्मल जाति की फलियों की लम्बाई भी 10–12 से.मी. रहती है और यह बुआई के 38 से 40 दिन बाद ही फलने लगती है।

● बरगुन्डी जाति की पत्तियां तो हरी रहती हैं। परंतु तना, शाखायें तथा पत्ती की शिरा तथा फलियां बरगुन्डी रंग की रहती है। मिट्टी की लम्बाई 12 से 18 से.मी. तक रहती है। पकाने पर इसका रंग हरा हो जाता है।

समस्या – मूंग की अति शीघ्र पकने वाली नई जातियां कौन सी हैं।

– कृष्ण पाल लोधी

समाधान– ● मूंग की दो अतिशीघ्र पकने वाली जातियों का विकास भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर द्वारा किया गया है।

● पहली जाति आई.पी. एम. 205–7 है जो आई.पी.एम.2–1 और ई.सी. 39889 के क्रास से बनी है। यह नई जाति 45 से 48 दिन में पककर तैयार हो जाती है।

● दूसरी जाति आई.पी.एम. 409–4 है जो पी.डी.एम. 288 और आई.पी.एम. 3–1 के क्रास से बनी है। यह जाति भी 45 से 48 दिन में पक कर तैयार हो जाती है।

● दोनों ही जातियां मूंग के पीले मोजेक वाइरस के प्रति प्रतिरोधी हैं। इनकी उपज क्षमता लगभग 8 क्विं. प्रति हेक्टर है।

समस्या– गन्ने के लाल सड़न रोग के बचाव एवं उपचार के उपाय सुझायें।

– मुरलीधर यादव

समाधान– गन्ने की लाल सड़न रोग पत्तियों से लेकर गन्ने की भीतरी सतह तक आक्रमण करता है यह रोग फफूंदजनित होता है। इस रोग के कारण इसकी गुणवत्ता पर असर होता है तथा सामान्य फसल की तुलना में गन्ने का विकास भी कम होता है। इसके बचाव के लिये निम्न उपाय करें।

●रोग रोधी जातियाँ जैसे को.– 87025, को. जवाहर 86–600, को.–94012 तथा को. 91010 को ही लगायें।

● गडेरियों का बुआई पूर्व गर्म हवा से उपचार करें।

● रोग रहित खेत का गन्ना लगाने हेतु चयन करें।

● 1 गडेरियों का उपचार करने के पूर्व 10 ग्राम ट्राईकोडर्मा/ लीटर पानी के घोल में 10 मिनट तक डुबोकर करें।

● जड़ी फसल में पूरा–पूरा उर्वरक दें तथा उर्वरक संतुलित होना चाहिये।

● पत्तियों में रोग के लक्षण दिखने पर उन्हें तोड़कर नष्ट करें।

समस्या– धनिये की फसल में भभूतिया रोग तथा सफेद रतुआ की रोकथाम के लिये क्या उपाय अपनायें।

– राम सोबनेर

समाधान– ● भभूतिया रोग की रोकथाम

के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरिसेन्स (पी.एफ–2) के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल या डाइनेफेप 2 मि.ली. प्रति लीटर या घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के मान से छिड़काव करें।

● सफेद रतुआ रोग जिससे धनिया के दानों में विक्रांति आकर वह लम्बे हो जाते है के लिए डाइथेन जेड–78 के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें।

● एक हेक्टर में 500 लीटर घोल छिड़कें तथा 15 दिन के अंतर से दोहराये।

● अगले वर्ष फसल लगाते समय बीज को स्यूडोमोनास फ्लोरिसेन्स 10 ग्राम/किलो बीज तथा ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोये।

निवेदन

समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.

समस्या-समाधान

कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) फोन- 0755-4248100,2554864

प्राकृतिक खेती – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

फसल चक्र और अंतरवर्तीय खेती

फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन क्या है, और यह पारंपरिक खेती में क्यों ज़रूरी है?

फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन में मिट्टी की हेल्थ को बेहतर बनाने, कीड़ों का प्रेशर कम करने और पोषण चक्र को बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक मौसम में अलग-अलग फसलें लगाना शामिल है।

प्राकृतिक खेती में मैं कौन सी फसलें उगाऊँ, यह कैसे तय करूं?

फसलों का चुनाव उनकी पोषण की जरूरतों, विकास की आदतों और स्थानीय जलवायु तथा मिट्टी की अनुकूलता के आधार पर करें।

क्या आप अंतरवर्तीय खेती का सिद्धांत समझा सकते हैं, और यह प्राकृतिक खेती में कैसे काम करता है?

अंतरवर्तीय खेती में एक ही खेत में दो या दो से ज़्यादा फसल की किस्मों को एक साथ लगाना शामिल है। यह जगह को संशोधित करता है, कीड़ों को कम करता है, और मिट्टी की हेल्थ को बेहतर बनाता है।

क्या फसलों के ऐसे खास मेल हैं जो भारतीय किसानों के लिए अंतरवर्तीय फसल में अच्छे से काम करते हैं?

सही मेल क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होते हैं, लेकिन आम उदाहरणों में अनाज के साथ फलियां या सब्जियों के साथ जड़ी-बूटियां लगाना शामिल है।

प्राकृतिक खेती में अंतरवर्तीय खेती मिट्टी की सेहत और फसल की पैदावार को बेहतर बनाने में कैसे मदद करता है?

अंतरवर्तीय खेती से जड़ प्रणाली में विविधता आती है, पोषण चक्र बेहतर होता है, मिट्टी का कटाव कम होता है, और मिट्टी की पूरी सेहत बेहतर होती है।

कृषक जगत

बागवानी सीरीज

साग-सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक — रु. 95 — कोड : 016
सब्जियों में पौध संरक्षण — रु. 75 — कोड : 017
मशरूम एक लाभ अनेक — रु. 45 — कोड : 019
मिर्च की उन्नत खेती — रु. 55 — कोड : 020
केला उत्पादन — रु. 70 — कोड : 025
गुलाब बहुरंगी संशोधित संस्करण — रु. 75 — कोड : 027
पपीता — रु. 55 — कोड : 031
अदरक — रु. 55 — कोड : 032
फलों की खेती — रु. 75 — कोड : 040
सजाएं फूलों से बगिया — रु. 65 — कोड : 041
घर की बगिया — रु. 95 — कोड : 050

डाक द्वारा मंगवाने हेतु निम्नलिखित जानकारी के साथ हमारे पते पर ड्राफ्ट/ मनीऑर्डर के साथ ऑर्डर कीजिए . किताब कोड नं. पर ✔ निशान लगाएं

016 ☐ 017 ☐ 019 ☐ 020 ☐ 025 ☐ 027 ☐ 031 ☐ 032 ☐ 034 ☐ 040 ☐ 041 ☐ 050 ☐

नाम _____
ग्राम _____ पोस्ट _____ तह. _____
जिला _____ फोन/मोबा. _____
कुल राशि _____ ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या _____
संलग्न ड्राफ्ट नं. _____ मनी आर्डर रसीद क्र. _____ वी.पी. भेजें ☐

संस्थाओं द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां खरीदने पर आकर्षक छूट. अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें.

कृपया ड्राफ्ट या मनीआर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम
14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011
फोन : 0755-4248100, 2554864, मो.: 9826255861, Email-info@krishakjagat.org
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास, इंदौर (म.प्र.) मो. : 9826021837

● निधि जोशी
joshinidhi894@gmail.com

आंवला

स्वास्थ्य लाभ एवं मूल्य वर्धित उत्पाद

आंवला एक अत्यंत पोषक और औषधीय गुणों से भरपूर फल है, जिसे आयुर्वेद में 'अमृत फल' की संज्ञा दी गई है। यह छोटा, हरा-पीला फल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले यौगिकों से भरपूर है और भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान में गहराई से निहित है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, खनिज तत्व और फाइबर पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पाचन सुधारने, त्वचा व बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तथा मधुमेह व हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में सहायक होते हैं। आंवले का नियमित सेवन समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही आंवले से विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार किये जाते हैं, जो न केवल इसके पोषण गुणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखतें हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय एवं रोजगार सृजन का भी महत्वपूर्ण साधन बनतें हैं।

भारत में आंवला का उत्पादन

भारत विश्व स्तर पर आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया के उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान के आंवला उत्पादन में अग्रणी होने के साथ विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर आंवले खेती की जाती है।

जलवायु और मिट्टी की आवश्यकताएं

आंवला उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पनपता है। यह शुष्क और अर्ध-शुष्क परिस्थितियों को सहन कर सकता है और मिट्टी की एक विस्तृत श्रृंखला-हल्के रेतीले दोमट से लेकर भारी मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है। पेड़ सूखा प्रतिरोधी है, जो इसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में खेती के लिए उपयुक्त बनाता है।

कटाई और उपज

आंवला का पेड़ रोपण के तीन से चार साल बाद फल देना शुरू कर देता है। कटाई का मौसम क्षेत्र के अनुसार भिन्न होता है लेकिन आमतौर पर अक्टूबर और फरवरी के बीच पड़ता है। फलों की उपज उम्र के साथ बढ़ती है, और एक परिपक्व पेड़ सालाना 50-70 किलोग्राम फल होता है।

आंवला की पोषण प्रोफ़ाइल

आंवला पोषक तत्वों का एक पावरहाउस है, जो इसे स्वास्थ्य के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक सुपरफूड बनाता है। इसकी प्रभावशाली पोषण प्रोफ़ाइल में शामिल हैं-

मैक्रोन्यूट्रिएंट्स

कैलोरी: कैलोरी में कम, 44 कैलोरी प्रति 100 ग्राम।

कार्बोहाइड्रेट: 10-11 ग्राम प्रति 100 ग्राम, मुख्य रूप से प्राकृतिक शर्करा के रूप में।

प्रोटीन: लगभग 0.9 ग्राम प्रति 100 ग्राम।

वसा: प्रति 100 ग्राम में 0.6 ग्राम से कम।

सूक्ष्म पोषक तत्व

विटामिन सी: आंवला विटामिन सी के सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोतों में से एक है, जिसमें प्रति 100 ग्राम में 600-700 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। यह विटामिन प्रतिरक्षा स्वास्थ्य, त्वचा की मरम्मत और कोलेजन संश्लेषण के लिए आवश्यक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट है।

खनिज: कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम आंवले में उच्च मात्रा में पाया जाता है।

पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनोइड्स: आंवले में गैलिक एसिड, एलाजिक एसिड और क्वेरसेटिन शामिल हैं, जो इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों में योगदान करते हैं।

अन्य बायोएक्टिव यौगिक पदार्थ

टैनिन: विटामिन सी को संरक्षित करने और रोगाणुरोधी गुण प्रदान करने में मदद करता है।

पेक्टिन: आंत की गतिशीलता में सुधार करके पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करता है।

आंवला के स्वास्थ्य लाभ

आंवला की पोषण संबंधी समृद्धि विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है-

इम्यूनिटी बूस्ट करता है

उच्च विटामिन सी सामग्री प्रतिरक्षा को बढ़ाती है, जिससे शरीर को संक्रमण से लड़ने और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। आंवला के एंटीऑक्सिडेंट ऑक्सीडेटिव तनाव का भी मुकाबला करते हैं।

पाचन स्वास्थ्य में सुधार करता है

आंवला फाइबर और पेक्टिन में समृद्ध है, जो की पाचन में सहायक, कब्ज को रोकने और एक स्वस्थ माइक्रोबायोम को बढ़ावा देता है। यह एक प्राकृतिक रेचक के रूप में भी कार्य करता है और अम्लता और गैस्ट्रिटिस के प्रबंधन में मदद करता है।

हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है

आंवला का नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल के स्तर, विशेष रूप से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। यह धमनियों में पट्टिका के गठन को रोककर और रक्त परिसंचरण में सुधार करके हृदय स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है।

रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है

आंवला मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसकी पॉलीफेनोल सामग्री ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करती है जो मधुमेह की जटिलताओं में योगदान देती है।

त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है

आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है, जो त्वचा की लोच और बालों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। यह मुँहासे और उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करने में भी मदद करता है।

वजन घटाने को बढ़ावा देता है

आंवला की कम कैलोरी सामग्री और उच्च फाइबर इसे वजन प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाते हैं। यह चयापचय को बढ़ाता है और वसा कम करने में सहायता करता है।

पुरानी बीमारियों को रोकता है

फल के शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट, मुक्त कणों को बेअसर करते हैं, जिससे कैंसर, गठिया और न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों जैसी पुरानी स्थितियों का खतरा कम हो जाता है।

दृष्टि और नेत्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है

आंवला में पाए जाने वाले विटामिन ए और कैरोटीनॉयड दृष्टि में सुधार करते हैं, मैकुलर अपघटन को रोकते हैं और मोतियाबिंद के जोखिम को कम करते हैं।

(अगले अंक में पढ़ें आंवला के उत्पाद)

सुबह का नाश्ता अच्छी सेहत के लिए बेहद जरूरी

सुबह का नाश्ता लोगों की सेहत को सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। आमतौर पर लोग जल्दबाजी और हड़बड़ी में सुबह का नाश्ता छोडक़र सीधा दोपहर के भोजन पर टूट पड़ते हैं। यह सेहत को नुकसान पहुंचाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक सुबह का नाश्ता अच्छी सेहत के हिसाब से बेहद जरूरी है। पूर्व में हुए शोधों में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सुबह का नाश्ता दिमाग और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद होता है।

ये हैं ब्रेकफास्ट के फायदे –

● सुबह का नाश्ता शरीर को ऊर्जावान बनाता है। नियमित नाश्ता करने वाले लोगों की पाचन क्षमता ठीक रहती है। ये लोग नाश्ता नहीं करने वाले लोगों की अपेक्षा अपना वजन भी जल्द घटा लेते हैं।

● सुबह नाश्ता करने वाले लोग अधिक प्रभावी और सजग तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं। इससे दिन की अच्छी शुरुआत होती है और मस्तिष्क को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है।

● सर्वे में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो बच्चे सुबह अच्छा नाश्ता करते हैं, स्कूल में उनका प्रदर्शन बेहतर होता है।

● अच्छे ब्रेकफास्ट में जूस शामिल होता है। लेकिन जूस के बजाय फल सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है।

● नाश्ते में फल को शामिल करें। विटामिन, खनिज और फाइबर होने के कारण यह संतुलित आहार माना जाता है।

● ब्रेकफास्ट को जल्दी – जल्दी में निपटाएं नहीं। इसमें पौष्टिक चीजों को भी शामिल करें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी है।

● ब्रेकफास्ट में फास्टफूड को शामिल मत करें। दिन की शुरुआत ऐसे खाने से न करें जो सस्ता, जल्द बनने वाला और सुविधाजनक हो।

● फलों का जूस पीते समय उससे मिलने वाली कैलोरी का भी ध्यान रखें। एक गिलास जूस में लगभग 80-100 कैलोरी होती है। जूस को पीने से पहले एक गिलास पानी पिएं। इससे आप कम जूस पिएंगे। जूस से ब्लड शुगर बढ़ता है।

● अगर आप ब्रेड पर मक्खन के साथ जैम-जैली लगाकर खाने के शौकीन हैं तो वसा युक्त खाने से परहेज करें। इसके बजाए फलों से युक्त कुछ खाएं जो वसा रहित होने के साथ ही पौष्टिक भी हो।

● अंडा खाते हैं तो उसके सफेद हिस्से को ही खाएं। एक पूरा अंडा और दो अंडे की सफेदी से बना आमलेट खा सकते हैं।

● नाश्ते में दलिया को शामिल करें। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के साथ ही यह कोलेस्ट्राल को घटाता है।

● नाश्ते में प्रोटीन जरूर शामिल करें। प्रतिदिन नाश्ता करने से मस्तिष्क को ताकत मिलती है।

पाक्षिक पंचांग

12 से 25 जनवरी 2026 तक
विक्रम संवत् 2082
माघ कृष्ण 9 से माघ शुक्ल 7 तक

दि.	माह	वार		तिथि/त्यौहार
12	जनवरी	सोम	माघ कृष्ण	9
13	जनवरी	मंगल	----------	10 लोहड़ी उत्सव
14	जनवरी	बुध	----------	11 मकर संक्रांति, खरमास समाप्त, षट्तिला एकादशी
15	जनवरी	गुरु	----------	12 तिल द्वादशी
16	जनवरी	शुक्र	----------	13 शिव चतुर्दशी, प्रदोष
17	जनवरी	शनि	----------	14
18	जनवरी	रवि	----------	30 मौनी अमावस्या
19	जनवरी	सोम	माघ शुक्ल	1
20	जनवरी	मंगल	----------	2 पंचक 1.48 रात से
21	जनवरी	बुध	----------	3 पंचक
22	जनवरी	गुरु	----------	4 विनायकी चतुर्थी व्रत, पंचक
23	जनवरी	शुक्र	----------	5 बसंत पंचमी, पंचक
24	जनवरी	शनि	----------	6 शीतलाष्टमी व्रत, पंचक
25	जनवरी	रवि	----------	7 नर्मदा जयंती, पंचक 12.7 दिन तक

खेती की अधिक जानकारी के लिए देखें
www.krishakjagat.org

जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मोबाइल ऐप पर कर्मयोगी वाटरशेड मॉड्यूल लॉन्च

जयपुर। पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। सचिवालय में आयोजित बैठक में पंचायती राज राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी भी उपस्थित रहे। पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मोबाइल ऐप पर कर्मयोगी वाटरशेड मॉड्यूल लॉन्च किया।

श्री दिलावर ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा निर्मित प्रशिक्षण वीडियोयुक्त यह ऐप विभागीय कार्मिकों के लिए उपयोगी होगा और जल संरक्षण को नई दिशा देगा। यह जल स्वावलंबन की ओर एक सशक्त कदम है। उन्होंने इस अभिनव पहल के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने मॉड्यूल निर्माण में सहयोग देने वाले 14 व्यक्तियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया।

क्या है कर्मयोगी वाटरशेड मॉड्यूल–विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में ली जाने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे अभियांत्रिकी ढांचे, डीपीआर MIS, गुणवत्ता, टेंडर, RTPP Rule आदि विषय वस्तुओं का सुलभ सरल भाषा में प्रशिक्षण सामग्री वीडियो के रूप में तैयार की गई है। यह सामग्री ई- लर्निंग का भाग है जो MJSA APP, विभाग के यूट्यूब चैनल पर सर्व सुलभ रहेगा।

विभाग ने अभी तक 38 वीडियो विभिन्न विषय वस्तु पर तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किए हैं। भारत सरकार की PMKSY वेबसाइट के 13 वीडियो एवं आईआईटी रुड़की खड़गपुर आदि संस्थाओं के 77 वीडियो और विभाग द्वारा संपादित विभिन्न सफलताओं की कहानियां आदि इस प्लेटफार्म पर एक साथ उपलब्ध रहेगी । श्री दिलावर ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, ऑडिट पेरा तथा विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा की।

बैठक में पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के निदेशक श्री मुहम्मद जुनैद एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

व्यक्तिगत क्लासीफाइड

विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-

- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि
- बीज ▪ औषधीय फसल

विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक

- अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक

डिस्प्ले क्लासीफाइड

विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.

कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेक्टर्स, तीर्थ यात्रायें, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।

कृषक जगत
की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.
(सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक)
62 62 166 222
www.krishakjagat.org @krishakjagat
@krishakjagatindia @krishak_jagat

पूगल बनेगा सौर ऊर्जा का नया हब

2450 मेगावाट क्षमता का होगा सोलर पार्क

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को निरन्तर गति दे रही है। इसी क्रम में बीकानेर जिले के पूगल में स्थापित किए जा रहे सोलर पार्क की निविदा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया गया है। इसमें बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 9 मार्च निर्धारित की गई है। इस निविदा में सौर ऊर्जा क्षेत्र की देश-विदेश की कंपनियां अपनी बोली प्रस्तुत करेंगी।

ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बताया कि पूगल सोलर पार्क में 2,450 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ 1,600 मेगावाट/6,400 मेगावाट-घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी। यह पार्क राज्य में सुनिश्चित और डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कंपनी इस परियोजना के लिए आधारभूत ढांचा विकसित कर रही है। इसके लिए 4,394 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। इसमें जो सोलर तथा बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित होंगी, वे राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के पारेषण तंत्र से कनेक्ट की जाएंगी। परियोजनाओं को 'बिल्ड ऑन ऑपरेट' (बीओओ) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं से उत्पन्न शत-प्रतिशत बिजली का क्रय 25 वर्षों के लिए

प्रमुख तिथियां

- **बोली डाउनलोड प्रारंभ:** 9 जनवरी 2026
- **साइट विज़िट:** 10 जनवरी 2026 से
- **प्री-बिड बैठक:** 22 जनवरी 2026
- **बोली जमा:** 9 मार्च 2026
- **बोली खोलना:** 12 मार्च 2026

17 हजार करोड़ रुपए का आएगा निवेश

राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा राज्य के डिस्कॉम्स के लिए किया जाएगा। इससे डवलपर्स को दीर्घकालिक राजस्व मिलना सुनिश्चित होगा।

पार्क को दो भागों में विकसित किया जाएगा। प्रथम भाग में 2,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के साथ ही 1,320 मेगावाट/5,280 मेगावाट-घंटे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का विकास होगा। दूसरे भाग में 450 मेगावाट सौर ऊर्जा तथा 280 मेगावाट/1,120 मेगावाट-घंटे ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित होगी। बोलीदाता दोनों लॉट में भाग ले सकते हैं। इसमें अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्यूफैक्चरर्स सूचीबद्ध सौर मॉड्यूल का उपयोग, साइबर सुरक्षा मानकों का पालन तथा जीपीएस-सक्षम स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना अनिवार्य होगी। हस्ताक्षर की तिथि से 24 माह के भीतर ऊर्जा उत्पादन शुरू करना होगा।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं से लगभग 17,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और लगभग 1,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जो राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 'यह मेगा निविदा' राजस्थान को ऊर्जा भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी बनाएगी। यह पीक ऑवर्स में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी और भारत के एनर्जी ट्रान्जिशन में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने देश-दुनिया के डवलपर्स को इस परिवर्तनकारी पहल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।

78 वर्ष
कृषक जगत राष्ट्रीय कृषि अखबार भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक
- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
⇨ वार्षिक रु. 600/- ⇨ दो वर्ष रु. 1000/-
⇨ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से **'कृषक जगत'** – प्रति सप्ताह ☐ भोपाल ☐ जयपुर ☐ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).

नाम .....
.....
ग्राम ..... पो. .....
डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : .....
वि.ख. ..... तह. .....
जिला ..... पिन ☐☐☐☐☐☐ राज्य .....
शिक्षा ..... भूमि ..... उम्र .....
ट्रैक्टर/मॉडल ..... फोन/मो. .....
ई-मेल .....
मेरा सदस्यता शुल्क रुपये ..... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/
मनीऑर्डर/क्र. ..... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम
कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php
Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793, Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861
कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

स्मार्ट खेती का दौर

क्या एआई किसान का नया साथी बनेगा ?

भारत की खेती आज एक अहम मोड़ पर खड़ी है। खेत में खड़ा किसान अब सिर्फ यह नहीं सोचता कि फसल कितनी होगी, बल्कि यह भी सोचता है कि बारिश समय पर होगी या नहीं, लागत कैसे निकलेगी, बाजार में सही दाम मिलेगा या नहीं। ऐसे समय में जब हर फैसला जोखिम से भरा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता–यानी एआई को खेती का नया सहारा बताया जा रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या एआई सच में किसान की ताकत बनेगा, या फिर यह भी एक ऐसी तकनीक साबित होगी जो शहरों में तो चर्चा बटोरती है, लेकिन गांवों तक आते–आते कमजोर पड़ जाती है?

● मयूर नरेंद्र पाटिल
वेस्ट निमाड़ एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लि.,
मो.: 9595068889

86 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत

आज एआई की बातें बड़ी–बड़ी बैठकों और सरकारी मंचों पर खूब होती हैं। ड्रोन, सैटेलाइट से मिली जानकारी, मिट्टी की जांच, अपने आप चलने वाली सिंचाई व्यवस्था और बीमारी पहचानने वाले ऐप–ये सब सुनने में बहुत आधुनिक लगते हैं। लेकिन ज़मीन की सच्चाई कुछ और ही कहती है। भारत के करीब 86 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं। उनके पास सीमित ज़मीन, सीमित आमदनी और सीमित संसाधन हैं। ऐसे में यह कहना कि एआई खेती की तस्वीर बदल देगा, उतना ही मुश्किल है जितना यह मान लेना कि गांव में 5 प्रतिशत आते ही कृषि क्रांति हो जाएगी।

एआई में संभावनाएँ हैं

फिर भी, एआई ने खेती में कुछ नई उम्मीदें ज़रूर जगाई हैं। आज मौसम की जानकारी पहले से ज्यादा सही मिल रही है, जिससे किसान सही समय पर बुवाई कर सकता है। ड्रोन से फसल की तस्वीर लेकर बीमारी का जल्दी पता चल जाता है, जिससे खर्च कम होता है और नुकसान भी घटता है। पानी की कमी वाले इलाकों में एआई आधारित सिंचाई तकनीक ने पानी बचाने का रास्ता दिखाया है। बाजार से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर मिलने से किसान को यह समझ आने लगा है कि कौन–सी फसल उसे फायदा दे सकती है। साफ है कि एआई में संभावनाएँ हैं।

गांवों में इंटरनेट की रफ्तार धीमी

लेकिन हर उम्मीद के साथ कुछ सवाल भी जुड़े हैं। आज भी कई गांवों में इंटरनेट की रफ्तार इतनी धीमी है कि ऐप खुलते–खुलते किसान का भरोसा ही टूट जाता है। बहुत से किसानों के पास स्मार्टफोन तो हैं, लेकिन वे इतने सक्षम नहीं कि भारी ऐप आसानी से चला सकें। ऊपर से ज्यादातर एआई प्लेटफॉर्म अंग्रेज़ी में हैं, जबकि किसान अपनी स्थानीय भाषा में ही सहज महसूस करता है। डिजिटल समझ बढ़ाने की बातें कागज़ों में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी भी पीछे है।

एआई पर भरोसा खतरे से खाली नहीं

इसके साथ ही, एआई पर जरूरत से ज्यादा भरोसा भी खतरे से खाली नहीं है। खेती हमेशा से प्रकृति के साथ तालमेल का काम रही है। स्थानीय मौसम, मिट्टी की आदत और कीटों का व्यवहार–इन सबकी समझ किसान अपने अनुभव से हासिल करता है। एआई अनुमान लगा सकता है, लेकिन हर बार सही नहीं हो सकता। इसलिए तकनीक को सलाहकार बनाना ठीक है, मालिक बनाना नहीं।

एआई तकनीक अभी सपना

एआई तकनीक का खर्च भी एक बड़ा रोड़ा है। ड्रोन सर्वे, सेंसर और स्मार्ट उपकरण आज भी ज्यादातर बड़े किसानों तक सीमित हैं। छोटे किसान के लिए यह तकनीक अभी सपना ही लगती है। जब किसान पहले से ही खाद, बीज और डीज़ल के दामों से जूझ रहा है, तो उससे यह उम्मीद करना कि वह महंगी तकनीक अपनाएगा, सही नहीं लगता।

एक और अहम मुद्दा है डेटा का। आज खेती से जुड़ा डेटा 'नया सोना' बन चुका है। मिट्टी, पानी, मौसम और फसल की जानकारी कंपनियों के लिए बहुत कीमती है। लेकिन किसान को यह शायद ही बताया जाता है कि उसका डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है और उससे फायदा कौन उठा रहा है। अगर नियम साफ नहीं हुए, तो एआई किसान को मज़बूत करने के बजाय उसे तकनीक पर निर्भर बना सकता है।

किसान को फायदा क्या मिलेगा

सबसे बड़ा सवाल यही है–किसान को इससे सीधा फायदा क्या मिलेगा? खेती की असली समस्या सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि सही दाम और बाजार तक पहुंच है। अगर एआई किसान को सही कीमत दिलाने में मदद करे, बिचौलियों का दबाव कम करे और जोखिम घटाए, तभी यह तकनीक वाकई काम की होगी। सिर्फ खेत से डेटा इकट्ठा करने से किसान की ज़िंदगी नहीं बदलती।

यह खतरा भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि अगर एआई आधारित खेती पूरी तरह कंपनियों के हाथ में चली गई, तो किसान का नियंत्रण कमजोर पड़ जाएगा। फैसले अगर मोबाइल ऐप लेने लगें, तो किसान सिर्फ उपयोगकर्ता बनकर रह जाएगा। भारत की खेती के लिए यह रास्ता खतरनाक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि एआई का इस्तेमाल किसान को सशक्त बनाने के लिए हो, न कि उसे नियंत्रित करने के लिए।

ज़रूरत के हिसाब से तकनीक तैयार करनी होगी

फिर भी, एआई को नकारना समाधान नहीं है। सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए, तो यह पानी बचाने, बीमारी रोकने और बाजार से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके लिए सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और निजी कंपनियों को मिलकर किसानों की ज़रूरत के हिसाब से तकनीक तैयार करनी होगी।

एआई को किसान का सच्चा साथी बनाने के लिए तीन बातें सबसे ज़रूरी हैं–गांवों में तेज़ और सस्ता इंटरनेट, सरल और किफायती तकनीक, और साफ व पारदर्शी नियम। सबसे अहम बात यह है कि खेती से जुड़ा डेटा किसान का ही माना जाए।

अंत में यही कहा जा सकता है कि एआई खेती का भविष्य बन सकता है, लेकिन तभी जब किसान उसकी केंद्र में हो। तकनीक तभी सफल होगी जब वह किसान के अनुभव और समझ के साथ मिलकर आगे बढ़े। एआई किसान का साथी बन सकता है–लेकिन यह फैसला किसान करेगा, कोई एल्गोरिदम नहीं।

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 की तैयारियों की समीक्षा

किसानों की आमदनी में वृद्धि से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत : श्री श्रीनिवास

प्रदेश के कृषक सीखेंगे कृषि क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवीन तकनीक एवं नवाचार

जयपुर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2026 के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, उन्हें कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि ग्राम के आयोजन से प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर इनके माध्यम से स्मार्ट फार्मिंग कर कृष क्षेत्र में अग्रणी बनेंगे।

मुख्य सचिव ने ग्राम के सफल आयोजन के लिए कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, राजस्व, उद्योग, पर्यटन आदि विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के लिए कहा। इस आयोजन में कृषकों की भागीदारी के लिए मुख्य सचिव ने कृषकों का पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा, जिससे प्रगतिशील किसान ज्यादा से ज्यादा भाग लें और नवीन तकनिकों एवं नवाचारों का फायदा ले सकें।

प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती मंजू राजपाल ने पीपीटी के माध्यम से ग्राम की तैयारियों पर प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि ग्राम के आयोजन में पूरे प्रदेश से 50 हजार से ज्यादा कृषक भाग लेंगे, जिसमें राज्य के एवं संबद्ध क्षेत्रों की कृषि क्षमताओं एवं संभावनाओं का प्रचार-प्रसार किया जायेगा, देश-विदेश में रोड शो का भी आयोजन किया जायेगा। इस आयोजन में कृषक वैज्ञानिक संवाद, कृषक गोष्ठियों, प्रदर्शनी, सेमिनार, कान्फ्रेन्स, क्रेता-विक्रेता बैठकों व बिजनस बैठक का आयोजन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में 250 से अधिक प्रदर्शक एवं कम्पनियां, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, 32 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडलों, कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर के संस्थानों एवं अन्य सरकारी व गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी होगी।

उल्लेखनीय है कि ग्राम के आयोजन का उद्देश्य विश्व स्तर पर उपलब्ध कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों और नवाचारों को प्रदेश में किसानों तक पहुंचाना है। जिससे प्रदेश के कृषक नवीन तकनीक अपनाकर अपनी उत्पादकता में वृद्धि कर सकेंगे और प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

बैठक में कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, राजस्व, उद्योग, पर्यटन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, वित्त, शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ती आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया गया।

सरकार ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 पर सुझाव मांगे

नई दिल्ली (कृषक जगत)। कृषि विभाग, ने वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का नया मसौदा तैयार किया है। इसका उद्देश्य वर्तमान कीटनाशक अधिनियम, 1968 तथा उसके तहत निर्मित कीटनाशक नियम, 1971 को प्रतिस्थापित करना है।

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 एक किसान-केंद्रित विधेयक है। इस संशोधित विधेयक में किसानों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने हेतु पारदर्शिता एवं अनुरेखण (ट्रेसबिलिटी) जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे किसानों के जीवन में सुगमता को बढ़ावा मिलता है। इसमें प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल माध्यमों के उपयोग सहित सुधार-उन्मुख प्रावधान किए गए हैं तथा नकली/अवमानक कीटनाशकों पर नियंत्रण के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।

अपराधों के निपटान हेतु कंपाउंडिंग के प्रावधान भी किए गए हैं, जिनमें निवारक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए उच्च दंड का निर्धारण राज्य-स्तरीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कीटनाशकों के बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए संशोधन किए गए हैं, जिससे जीवन की सुगमता और व्यवसाय करने की सुगमता के बीच संतुलन स्थापित होता है। इस विधेयक में परीक्षण प्रयोगशालाओं के अनिवार्य प्रत्यायन का भी प्रावधान है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को केवल गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक ही उपलब्ध हों। पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का मसौदा तथा निर्धारित प्रारूप मंत्रालय की वेबसाइट https://agriwelfare.gov.in पर उपलब्ध है।

मसौदा विधेयक और उसके प्रावधानों पर सभी हितधारकों तथा आम जनता से टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित किए हैं। टिप्पणियाँ/सुझाव ई-मेल द्वारा pp1.pesticides[at]gov[dot]in /rajbir.yadava[at]gov[dot]in / jyoti.uttam[at] gov [dot]in पर एमएस वर्ड या पीडीएफ प्रारूप में 4 फरवरी 2026 तक भेजे जा सकते हैं।

50 वर्षों से निरंतर प्रकाशित
कृषक जगत
डायरी - 2026
बुकिंग प्रारंभ
नए आकार, नए कलेवर में
(एग्जीक्यूटिव डायरी)

कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए संदर्भ ग्रंथ
वर्ष भर कृषि सेवाओं और उत्पादों के
प्रचार हेतु सर्वोत्तम माध्यम

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान कृषि पर विशेष जानकारी
विज्ञापन एवं डायरी खरीदी के लिए संपर्क करें
• इंदौर - सचिन बोन्द्रिया : 9826021837 • भोपाल - अजय बोन्द्रिया : 9826255861
• इंदौर कार्यालय : 9826024864 • रायपुर - प्रेमप्रकाश सुल्लेरे : 9826255862
• नई दिल्ली व जयपुर - निमिष गंगराड़े : 7387422952
• ई-मेल : info@krishakjagat.org • वेबसाइट : www.krishakjagat.org